

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

ये यजल एवं स्वच्छता अनुभाग—१

देहरादून : दिनांक २२ सितंबर, २०१७

विषय: उत्तराखण्ड जल संस्थान के सेवारत कार्मिकों/पेशनरों को राज्य कर्मचारियों की भाँति दिनांक ०१.०१.२०१६ से सातवां वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त विभाग (व०आ०-सा०नि०) के संकल्प संख्या—२८९/XXVII (7)३०(७)/२०१६, दिनांक २७.१२.२०१६ एवं अधिसूचना संख्या—२९०/XXVII(7)५०(१६)/२०१६, दिनांक २८.१२.२०१६, शासनादेश संख्या—२९१/XXVII(7)३०(८)/२०१६, दिनांक २९.१२.२०१६, शासनादेश संख्या—२६६/४५/XXVII(१०)/२०१६, दिनांक ३०.१२.२०१६ तथा शासनादेश संख्या—२६७/४५/XXVII(१०)/२०१६, दिनांक ३०.१२.२०१६ के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या—११८५/वि०अनु०/०२/बोर्ड अनु० (१७ वी) / २०१७-१८, दिनांक २०.०५.२०१७ के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड जल संस्थान के सेवारत कार्मिकों/पेशनरों को दिनांक ०१.०१.२०१६ से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सातवां वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड द्वारा पारित वेतन मैट्रिक्स/वेतनमान/पेशन इस प्रतिबन्ध एवं शर्त के साथ अनुमन्य किया जाता है कि इस सम्बन्ध में होने वाला कोई भी परिवर्तन शासन की अनुमति से ही किया जाएगा।
२. उत्तराखण्ड जल संस्थान में सातवां वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप अवशेष वेतन का भुगतान अधिसूचना संख्या—२९०/XXVII(7)५०(१६)/२०१६, दिनांक २८.१२.२०१६ में निहित व्यवस्थानुसार दिनांक ०१.०१.२०१७ से नगद देय होगा तथा दिनांक ०१.०१.२०१६ से ३१.१२.२०१६ तक का अवशेष वेतन भत्तों एवं एरियर के भुगतान हेतु पृथक से आदेश किये जायेंगे।
३. उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्मिकों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०एस०) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—११/XXVII (7)३०(१४)/२०१७, दिनांक १७.०२.२०१७ में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।
४. उत्तराखण्ड जल संस्थान की सीधी भर्ती के पदों को फीज करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती/चयन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि परियोजना के संचालन हेतु कार्मिकों की आवश्यकता है एवं जिन पदों पर चयन की प्रक्रिया गतिमान है, ऐसे पदों पर भर्ती/चयन हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए आवश्यक पदों पर ही भर्ती/चयन की कार्यवाही की जाय, जिन पदों पर आउटसोर्स से तैनाती का कार्य लिया जा रहा है, ऐसे कार्मिकों को निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार नियत मानदेय का भुगतान किया जाय, भविष्य में उत्तराखण्ड जल संस्थान में स्वीकृत पदों की परिधि में ही आउटसोर्स कार्मिकों की तैनाती की जायेगी।
५. इस सम्बन्ध में उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय के आधार पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों में दिए गए निर्देशानुसार उत्तराखण्ड जल संस्थान के सेवारत कार्मिकों/पेशनरों को दिनांक ०१.०१.२०१६ से सातवां वेतनमान लागू किए जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्मिकों को सातवां वेतनमान

अनुमन्य किये जाने पर वित्तीय व्यय—भार जल संस्थान द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से वहन किया जाएगा तथा इस हेतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी और न ही राज्य सरकार से पुनरीक्षित वेतनमान की अन्तर की धनराशि की मांग की जाएगी। उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा मितव्यता सुनिश्चित करते हुए आय हेतु अपने संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।

2— यह आदेश वित्त विभाग के अशा०प०सं०—१६७ / xxvii(10) / २०१७, दिनांक २२.०९.२०१७ में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या : १२५८ / उन्तीस (१) / २०१७ / (०२ अधिक) / २०१७ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निजी—सचिव, पेयजल मंत्री को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. निजी—सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. वित्त (वे०आ०—सा०नि०) अनु०—७, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—४।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।